Extension of Railway Lines in Mining Areas of Bihar

*207. SHRI N. K. SINHA : Will the Minister of RAILWAYS (RAIL MANTRI) be pleased to state :

(a) the proposals of the Government of Bihar for extension of Railway lines in mining areas of Bihar State during the Fourth Five Year Plan, separately for iron-ore graphites and lime-stone areas ;

(b) whether the proposals have been accepted by his Ministry and the Planning Commission ; and

(c) when these proposals are likely to be implemented ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) 3 proposals have been received from the Government of Bihar for extension of railway lines in iron-ore mining areas in the Fourth Plan. No proposals have separately been received for graphite and limestone areas.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

किशू बांध परियोजना का निर्माण-कार्य

*208. श्री राम जन्म विकल : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशू बांध परियोजना कब तक आरम्भ हो जायगी और इस परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी विशेष योजनाएं होंगी ;

(ख) उक्त परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है ;

(ग) इस परियोजना से किन-किन राज्यों को लाभ होगा ; और

(घ) इस परियोजना के लिए किन-किन राज्यों से सहयोग मांगा गया है और उस सहयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार किशाऊ बांध परियोजना का अनुसंधान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा बनाये गए प्राथमिक प्रस्तावों के अनुसार परियोजना में दिल्ली के लिए पीने के पानी की आवधित नियमित सप्लाई के इस्तेमाल के लिए और विद्युत उत्पादन हेतु लगभग 800 फुट ऊंचा एक राक-फिल बांध और यमुना से सिंचाई शामिल है। राज्य के इन्जीनियरों का मोटा अंदाजा यह है कि इस पर 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये तक लागत आएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्तावों की हाल ही में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री, मुख्य मंत्री, हरियाणा, सिंचाई और विद्युत मंत्री, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वित्त और राजस्व मन्त्री, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद द्वारा, जांच की गई थी। जल-सचय के लिए टोंस नदी पर एक बांध बनाने की आवश्यकता पर आम करार हुआ है। इन राज्यों के इंजीनियरों (सिंचाई) और (जलविद्युत) और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के प्रवर इंजीनियरों से कहा गया है कि वे बांध के लिए कुछ अन्य संभावित स्थलों की जांच करें, आगे जल-विज्ञान संबंधी अध्ययन करें और जल-संचय को नियत करें और दिल्ली की जल-सप्लाई के लिए आवश्यक जल की मात्रा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के विस्तार के लिये शेष जल के इस्तेमाल और उस तरीके पर विचार-विमर्श करें जिससे इस जल को पहुंचाया जाए। इंजीनियरों से यह भी कहा गया है कि वे परियोजना में उत्पादन की जाने वाली विद्युत के बंटवारे और उस अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन के बारे में भी विचार-विमर्श करें जोकि अनुप्रवाह की मौजूदा रन-आफ-दि-रिवर परियोजनाओं पर संभव होगी और वे अन्य संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श करें।